साप्ताहिक
Live not just breaTHE

# दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

वर्ष : 5, अंक : 33 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 8 से 14 अप्रैल 2020 पेज : 4 कीमत : 3 रुपये

## कोरोना रिट्रीट: Exit Plan लॉक्डाउन के बाद

डॉ सोनल मेहता

उम्मीद करते हैं 14 अप्रैल को हम लोग लॉकडाउन से बाहर आ जाएँगे ऐसा सरकार और कुछ अन्य प्रबुद्ध लोगों का मानना है. प्रधानमंत्री जी ने आप और हम से इस अवधि को बढ़ाने ना बढ़ाने के बारे में सलाह माँगी है. पर एक बात तो तय है 14 अप्रैल या उसके बाद जब भी लॉकडाउन खुलेगा, सामाजिक और आर्थिक व्यवहार पहले जैसा तो नहीं रहेगा. उसमें कई बदलाव आएंगे। करोना के कैरियर आने वाले समय तक रहेंगे वातावरण में, जब तक कि वह खुद अपनी मौत ना मर जाए, या जब तक कि कोई टीका ना निकले उस समय तक सावधानी ही सुरक्षा है कुछ सुझाव लॉकडाउन के बाद के लिए-

1) 14 अप्रैल तक वो शहर चिन्हित हो जाएंगे जो कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं, उन जगहों पर लॉक डाउन अविधि बढ़ाई जाए और यहां नियंत्रित- प्रतिबंधित आवागमन सुनिश्चित किया जाए

2) युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, अस्पतालों और हेल्थ वर्कर को मुहैया कराए जाएं जैसे- थर्मल स्क्रीनिंग पीपीई, वेंटीलेटर आदि . क्षेत्रवार आइसोलेशन वार्ड चिन्हित किए जाएं जिससे प्रभावित लोगों को तुरंत क्वॉरेंटाइन किया जा सके।

3) उन जगहों से जो कोरोना हॉटस्पॉट नहीं है वहां से लोग डाउन हटने के बाद धारा 144 लगाई जानी चाहिए और हर तरह के आयोजनों सांस्कृतिक धार्मिक और राजनैतिक पर आगामी आदेश तक रोक लगाई जाए।

4) मास्क, ग्लव्स तथा सैनीटाईज़र्स की उपलब्धता बढ़ाई जाए तथा अनिवार्य किए जाएं और लोगों के बीच जागरूकता अभियान समय-समय पर आयोजित किए जाएं।

5) सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी स्थल मॉल रेलवे स्टेशन आदि पर थर्मल स्क्रीनिंग, आने वाले कुछ समय के लिए अनिवार्य कर दी जाए।

6) लेबर ला में संशोधन करते हुए बाजार सातों दिन खोले जाएं और उनके खुले रहने का समय बढ़ाया जाए जिससे लोग अलग-अलग समय पर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें.

7) निजी क्षेत्र को संभलने में समय लगेगा इसलिए सरकार को ही कुछ समय तक लोगों को रोजगार देना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाकर.

8) एक ऐसा एप बनाना चाहिए जिससे अकुशल बेरोजगारों को, जो घर से दूर है और जिनका जनधन खाता भी नहीं है उन तक राशन पहुंचाया जाए जो अधिकृत परीचय पत्र देख कर दिया जाए, जिससे अवान्छित लोग उसका फायदा ना उठा सके.

9) भारत सरकार और कर्ज़ ले तथा अपनी कर्ज सीमा को बढ़ाएं, 69% से ज्यादा जैसा की अन्य देशों की है उनकी जीडीपी के मुकाबले. उदाहरण जापान की ढाई सौ परसेंट अमेरिका की 108%. ज्यादातर विकसित देशों की डेब्ट अगेंस्ट जीडीपी सौ परसेंट से ज्यादा है।

10) सबसे महत्वपूर्ण- केंद्र और राज्यों को आपसी राजनैतिक मतभेद भुलाकर एक ही पायदान पर, अभी के जैसे साथ खड़े रहना है, करोना से लड़ाई में. साथ ही चुनाव आयोग भी वर्ष 2020 में सभी चुनाव आगामी वर्ष के लिए टाल दें जिससे राजनैतिक दलों के बीच सौहार्द ना बिगड़े।

यदि यही कुछ उपाय अपना ले तो जैसे लॉक डाउन सफल किया है वैसे ही हम भारतीय खुलापन भी परिपक्वता से पूर्ण करेंगे

**जय विश्व! जय भारत!**

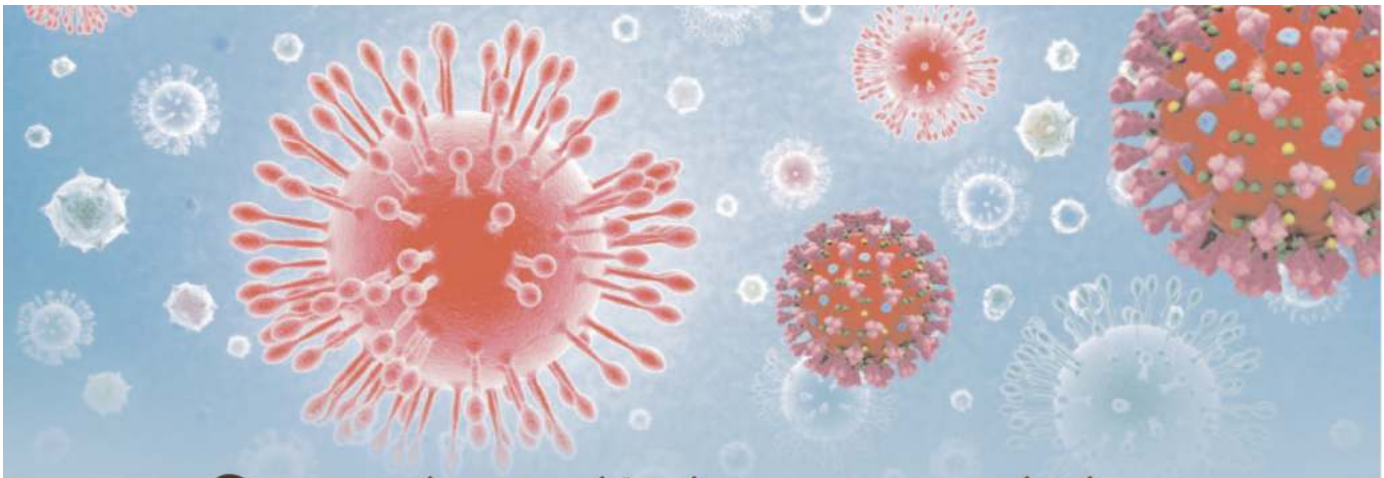

# महिला योद्धाओं से हारता कोरोना

**भारत** की सभी महिला योद्धाओं के लिए परीक्षा की घड़ी है। कोरोना जहां विपदा लेकर आया है, वहीं यह आपसी सामंजस्य लेकर भी आया है। जिन घरों में सभी सदस्य एक साथ यदा-कदा ही दिखते थे। अब वह सभी एक साथ रहने को विवश है। मतलब साफ है भारत में दूर जा रही परम्पराएं अब वापस आती दिख रही है। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया। कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम देखने को मिल रहे है। अच्छे परिणामों की बात करें तो प्रदूषण कम हुआ है, पारिवारिक मेल-जोल बढ़ा है, लोगों का दूसरों की जिंदगी में ताका-झांकी कम हो गयी है। सबसे दूरी बढ़ाकर लोग अपने परिवार तक सीमित रहने को संकल्पित दिख रहे है लेकिन इस बीच महिलाओं की भूमिका में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। कोरोना ने घरलू महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। उन्हें अब पहले से ज्यादा पकवान पर ध्यान देना पड़ रहा है।

जो महिलाएं आमतौर पर घर से बाहर रहने को अभ्यस्त थी उन पर तो जैसे कहर टूट पड़ा हो। लॉकडाउन की स्थिति में न तो कामवालियां आ रही है, न ही बाहर कहीं डिनर पर ही जाने का रास्ता है। एक-दो दिन की बात हो तो शायद घर संभाल हो जाता मगर घुम्मकड़ प्रवृति की महिलाओं के लिए लॉकडाउन मुश्किल भरा है। ना कोई किटी, न इवनिंग पार्टी, ना ब्यूटीपार्लर। ऐसे में टाइम पास के लिए घर का काम करना और बच्चे संभालने जैसे काम हाई प्रोफाइल औरतों को सूट नहीं कर रहा। ऊपर से सास बहू के सारे सीरियल भी बंद हो चुके है। वे भी रामायण और महाभारत देख रही है। इसी बहाने उम्मीद है, उन्हें भारतीय परंपरा और संस्कृति का ज्ञान होगा। जिसे वे लॉक डाउन खत्म होने पर अपने और अपने परिवार के बीच लागू कर सकेंगी।

कामकाजी महिलाओं के लिए भी कोरोना ने नाक में दम कर रखा है। अब तो वीकेंड भी गया, साथ ही ऑफिस वाली गपशप, कानाफूसी भी ना रहे। घर के कामकाज की आदत ना होने के कारण अवसाद बढ़ गया है। ना ही फोन पर इधर की उधर करने की ही सहूलियत है। जिससे वे अपना मन का बोझ हल्का कर सके। पूरी फैमिली साथ होने के कारण उनकी निजता धरी की धरी रह गयी है। मगर उन महिलाओं के लिए कोरोना सुनहरा अवसर लेकर आया है। जिन्हें ऑफिस से छुट्टी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। माएं जो अपने बच्चों को देखने, उनके साथ समय बिताने को तरस जाती थी, उनके लिए कोरोना बीमारी नहीं सौगात है। बीमारी से घर का सामंजस्य बढ़ता है, बच्चे घर के बूढ़े मां बाप के साथ वक्त बिता रहे है, नाते-नातिन ,पोते-पोतियां अपने दादा-दादी, नाना-नानी से लोरियां और कहानियां सुन रहे है। पूरा परिवार साथ है, भोजन और बातें करता है। एक दूसरे का हाल समाचार-खैरियत की दुआएं करने लगता हो तो यह इसका सकारात्मक पक्ष है। इस बीच जो अपने परिवार से दूर है, अकेले है, उन्होंने बहुत कुछ गवां दिया है। ऐसा पहली बार है, जब स्कूल कॉलेज, मार्केट, रेल, बसे, ऑफिस सभी बंद हैं। शायद ही ऐसा मौका कभी आये।

# कोरोना टेस्ट के लिए पैसा न वसूलें प्राइवेट लैब- सुप्रीम कोर्ट

**नईदिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि कोरोनावायरस से होने वाली बीमारी (कोविड 19) का टेस्ट मुफ्त में होना चाहिए। इसके लिए सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि लोगों को टेस्ट के लिए भुगतान न करना पड़े, बल्कि सरकार की ओर से प्राइवेट लैब को टेस्ट का पैसा दिया जाए।

इससे पहले सरकार ने प्राइवेट लैब को कोविड-19 टेस्ट की इजाजत देते हुए कहा था कि वे मरीजों से 4500 रुपए शुल्क ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी एक यौद्धा हैं और उनकी व उनके परिवारों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राइवेट लैब द्वारा शुल्क न वसूलने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सरकार विचार करेगी। अभी देश में 118 लैब की रोजाना लगभग 15000 टेस्ट क्षमता है। जो कम है, इसलिए लगभग 47 प्राइवेट लैब को टेस्ट की इजाजत दी जा रही है। सुधी ने डाउन टू अर्थ से कहा कि अदालत पूरी तरह से इस पक्ष में है कि लोगों से शुल्क न वसूला जाए। यहां यह उल्लेखनीय है कि 12 मार्च को इंडियन कौंसिल औफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा था कि प्राइवेट लैब संचालक चाहते हैं कि उन्हें भी कोरोना टेस्ट की इजाजत दी जाए। इसलिए उन्हें इजाजत देने का निर्णय लिया गया है। आईसीएमआर ने प्राइवेट लैब संचालकों से कहा था कि वे मुफ्त में कोरोना जांच करें। लेकिन कुछ देर बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्राइवेट लैब संचालकों को 4,500 रुपए तक वसूलने की इजाजत दी जाती है। सुधी ने अपनी याचिका में कहा था कि सरकार के पास इस महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

# बड़े वानरों के लिए खतरा बना कोरोनावायरस-विशेषज्ञ

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोरोनावायरस से दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ-साथ बड़े वानरों को भी खतरा है। इनमें चिंपांजी, बोनोबोस, गोरिल्ला और वनमानुष शामिल हैं। ये बड़े वानर सांस की बीमारियों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।

25 अध्ययनकर्ताओं के एक समूह ने कोरोनावायरस बीमारी (कोविड-19) के खतरों को देखते हुए सुझाव दिया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व चिड़ियाघरों में लोगों के जाने पर पाबंदी लगानी चाहिए या लोगों की संख्या सीमित कर देनी चाहिए।

अमेरिका की एमोरी विश्वविद्यालय के रोग पारिस्थितिक विशेषज्ञ और अध्ययनकर्ता थॉमस गिलेस्पी कहते हैं कि कोविड-19 से बड़े वानरों के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। यह अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

कुछ देशों ने पहले ही इन बड़े वानरों के रहने वाली जगहों पर लोगों के जाने तथा पर्यटन पर रोक लगा दी है।

चिंपांजी, बोनोबोस और गोरिल्ला उप-सहारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में रहते हैं, और वनमानुष इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षावनों के मूल निवासी हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने चिम्पांजियों और बोनोबोस को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है, जबकि गोरिल्ला और वनमानुष अधिक लुप्तप्राय प्रजाति है। ये वानर पहले से ही इनके रहने की जगहों को छीने जाने, अवैध शिकार के कारण खतरे में हैं।

शोधकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों में सामान्य सर्दी जैसे वायरस के हल्के प्रभाव हैं, अगर इन जंगली वानरों के संपर्क आते हैं तो ये जानवर मर भी सकते हैं। विशेषज्ञों को डर है कि यह बड़े वानरों के लिए विनाशकारी हो सकता है।

अभी तक के साक्ष्यों से पता चलता है कि कोविड-19 उन लोगों द्वारा फैलाया जा सकता है, जिनमें हल्के लक्षण भी होते हैं।

गिलेस्पी कहते हैं कि कर्मचारियों को उन अभयारण्यों में रहना चाहिए, लेकिन उनकी कर्मचारियों की संख्या की जानी चाहिए और इन कर्मचारियों को कोरोनावायरस संक्रमण से खुद को बचा कर रखना चाहिए। गिलेस्पी आईयूसीएन के एक सदस्य के रूप में उन्होंने संगठन में बड़े वानरों की आबादी में स्वास्थ्य निगरानी और रोग नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम दिशानिर्देश बनाने में मदद की है।

अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि हमें इन बड़े वानरों को लोगों के द्वारा फैलाए जाने वाले रोगाणुओं से बचाने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। इन संकटग्रस्त प्रजातियों पर हमारी गतिविधियों से पड़ने वाले खराब प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

# पर्यावरण आज की समस्या है कल की नहीं

भारत की नदियों में पानी कुछ ही दशकों में नाटकीय रूप से कम हो गया है। कुछ नदियां और झरने पूरी तरह से सूख गए हैं। सौभाग्य से, हमारी नदियां ज्यादातर जंगलों से पोषित हैं, हिमनद से नहीं - जब हमारा मन चाहे, हम हिमपात नहीं करा सकते, लेकिन हम जंगलों में वनस्पतियों को पुनः कायम कर सकते हैं।

### पेड़ों, मिट्टी और नदियों का संबंध

भारत में वर्षा औसतन पैंतालीस दिन होती है। उन पैंतालीस दिनों में जो भी पानी गिरता है, उसे हमें धरती में 365 दिन तक रोककर रखना होता है और धीरे-धीरे नदियों और दूसरे जलाशयों में रिसकर जाने देना होता है। आप धरती में पानी सिर्फ तभी रोककर रख सकते हैं अगर मिट्टी में जरूरी जैविक तत्व हों। आम तौर पर, यह समझा जाता है कि किसी मिट्टी को मिट्टी कहने के लिए उसमें कम से कम दो प्रतिशत जैविक तत्व होने चाहिए, लेकिन आज भारत की लगभग पच्चीस प्रतिशत जमीन में जैविक तत्व बस 0.05 प्रतिशत ही बचा है। इसका मतलब है कि हम समृद्ध मिट्टी को बहुत तेजी से रेत और रेगिस्तान में बदल रहे हैं। आज, अगर आप भारत के ऊपर से उड़ते हैं, तो आप अधिकतर भूरी, बंजर जमीन और बहुत कम हरे-भरे इलाके देखेंगे।

तो हम जैविक तत्व को वापस कैसे डालें? यह कहां से आता है? इसके लिए एकमात्र स्रोत पशुओं का गोबर और पेड़ों के पत्ते हैं। क्या इसका मतलब है कि हमें हर जगह जंगल वापस लाने होंगे? यह संभव नहीं है, लेकिन हमने एक आसान समाधन का प्रस्ताव रखा है कि नदी घाटी की 25 प्रतिशत जमीन को, जो सरकार के कब्जे में है, जंगल में बदल देना चाहिए - सिवाय उनके जिन्हें अगले पचास सालों में विकास के लिए निर्धारित किया गया है। बाकी जमीन खेती की जमीन है। यहां पर, एकमात्र तरीका कृषिवानिकी या पेड़ों पर आधारित खेती का है।

### कावेरी पुकारे - उष्णकटिबंधीय दुनिया के लिए परिवर्तन लाने वाला अभियान

अगर हम किसानों को पेड़ों पर आधारित खेती के लिए प्रोत्साहित कर सकें, तो पेड़ों से जैविक तत्व, और खेतों के पशुओं का गोबर नदियों और मिट्टी को पुनर्जीवित देगा। गरीब किसानों के लिए भी यह एक बहुत लाभदायक उद्यम होगा। इसलिए, यह पर्यावरण बनाम अर्थव्यवस्था नहीं है; नदी घाटी का पर्यावरण जमीन के मालिक के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। यही हमारे कावेरी पुकारे अभियान का सार है।

### कावेरी पुकारे कावेरी नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान

कावेरी पुकारे कावेरी नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान है। इस नदी में पानी खतरनाक ढंग से 40 प्रतिशत से अधिक कम हो गया है। हम किसानों को कृषिवानिकी की ओर ले जा रहे हैं और कावेरी नदी घाटी में 2.42 अरब पेड़ लगा रहे हैं। यह एक तिहाई घाटी को पेड़ों से ढंक देगा और नदी में बहाव बढ़ जाएगा। पेड़ लगाने के साथ-साथ बीच में दूसरी फसल उगाने के इस तरीके से किसानों के लिए कई लाभ हैं, जिनमें मिट्टी की उर्वरता में सुधार, फसल की बेहतर उपज, और जमीन में पानी का स्तर बढ़ना शामिल हैं। लेकिन सबसे बढ़कर, फल, लकड़ी और पेड़ के दूसरे उत्पादों के बिकने से किसान की आय कई गुना बढ़ जाती है। तमिलनाडु में, हमने 69,760 किसानों को पेड़ आधारित खेती में लगाया है और पांच से सात सालों में उनकी आय 3 से 8 गुना बढ़ गई है। एक बार जब हम इसे लाभदायक सिद्ध कर देते हैं, और यह कावेरी घाटी में बड़े पैमाने पर लागू करने योग्य है, तो इसे स्वाभाविक रूप से दूसरी नदियों के लिए दोहराया जा सकता है। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि उष्णकटिबंधीय दुनिया के लिए भी परिवर्तन लाने वाला अभियान है।

# सदी के अंत तक गंगा डेल्टा क्षेत्र के जल स्तर में होगी 85 से 140 सेमी तक की वृद्धि

साल 2100 तक डेल्टा के क्षेत्र के जल स्तर में 85 से 140 सेमी तक की वृद्धि हो सकती है। फ्रांस की सीएनआरएस, आईआरडी, बीआरजीएम, ला रोचेल्ले यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी देस एंटिलेस, और बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए गए एक अध्ययन के बाद यह दावा किया गया है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जल-स्तर में वृद्धि, भूमि के जल में समाने के बेहतर अनुमान लगाकर भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के बारे में बताया है। यह अध्ययन पीएनएएस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे घनी आबादी वाला डेल्टा है। ये डेल्टा जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील स्थानों में से एक है। यहां जल स्तर के बढ़ने की सीमा और प्रभाव को खराब रूप में देखा जाता है। यह क्षेत्र, जो बांग्लादेश के दो तिहाई हिस्से और पूर्वी भारत का हिस्सा है, पहले से ही नियमित रूप से बाढ़, तीव्र मानसून वर्षा, समुद्र के बढ़ते स्तर, नदी के प्रवाह और यहां भूमि पानी में समाने के कारण घट रही है। हालांकि, इन विभिन्न कारकों को अलग करना मुश्किल है। इसके अलावा, जल स्तर के अब तक लगाए गए पूर्वानुमान स्थानीय माप पर आधारित हैं।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, शोधकर्ताओं ने डेल्टा के चारो ओर पानी और समुद्र के स्तर को मापने के लिए 101 गेजों से ली गई मासिक रीडिंग का विश्लेषण किया। स्थानीय प्रभावों को अलग करने और गेज के बीच गुणवत्ता के अंतर को पूरा करने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों के आंकड़े एकत्र करके, उन्होंने जल-स्तर में बदलाव के लिए सटीक अनुमान लगाए है। 1968 से 2012 के बीच, जल स्तर में औसतन 3 मिमी प्रति वर्ष की वृद्धि हुई, वैश्विक समुद्री स्तर में औसत वृद्धि इसी अवधि के दौरान 2 मिमी प्रति वर्ष रही।

इसके बाद उन्होंने भूमि के घटने का अनुमान लगाया, जिसे समुद्र के समतल स्तर से घटाकर प्राप्त किया गया, जो पहले प्राप्त सापेक्ष जल स्तर का माप था। उनकी गणना के अनुसार, 1993 और 2012 के बीच डेल्टा में अधिकतम भूमि में 1 से 7 मिमी / वर्ष का घटाव था। ये मान कुछ स्थानीय मापों (जैसे ढाका में 1-2 सेंटीमीटर / वर्ष) से कम हैं, जिनका उपयोग अब तक एक संदर्भ के रूप में किया गया है।

यदि इसी दर से भू-स्तर में घटाव जारी रहा, और ग्रीनहाउस गैस में कमी के परिदृश्य के तहत, क्षेत्र के आधार पर, डेल्टा में जल-स्तर में वृद्धि, 1986-2005 की अवधि की तुलना में सदी के अंत तक 85 से 140 सेमी तक पहुंच सकती है। यह नवीनतम आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुमानों से दोगुने से अधिक है, इसमें भूमि के घटाव को ध्यान में नहीं रखा गया था।

इस अध्ययन से गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा में जल स्तर के पूर्वानुमानों में सुधार करने में मदद मिलेगी, और इसके निकट रहने वाले 20 करोड़ लोगों को इससे प्रभावित होने से बचाया जा सकता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर ( म.प्र. ) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर ( म.प्र. ) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008